क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 326, बुधवार, 26 दिसम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

महज 76 सेकंड में 14 फ़ीट की दीवार फांदकर बालिकागृह से भाग निकली बच्ची, घटना से हड़कंप

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोतीनगर बालिकागृह से रविवार की तड़के सुबह 15 साल की बच्ची मजह 1 मिनट 16 सेकंड में 14 फ़ीट की दीवार फांदकर छत के रास्ते भाग निकली। बच्ची के गायब होने की सूचना मिलते ही राजकीय बालिकागृह में हड़कंप मचा गया। सीसीटीवी कैमरे में बच्ची के बालिकागृह से भागने का वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। नाका थाने के इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह ने बताया कि यह लड़की ट्रेनों में भीख मांगती थी। जिसका रेस्क्यू करके चाइल्डलाइन ने 18 दिसंबर को राजकीय बालिका गृह को सौंपा गया था। महज 4 दिन में ही लड़की बालिका गृह से भाग गई। दूसरी तरफ बाल गृह का लगातार अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा।

टीपीडीडीएल का महिला संचालित ग्राहक सेवा केंद्र शुरू

नई दिल्ली। बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) ने पूरी तरह महिलाओं की ओर से संचालित ग्राहक सेवा केंद्र की शुरुआत की है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि यह केंद्र पीतमपुरा में स्थित है और इसका प्रबंधन पूरी तरह महिलाओं की टीम करेगी। इन महलिाओं को बिजली आपूत्तर आवेदनों का निपटान तथा मासिक बिल भुगतान समेत अन्य कायरे के लिये प्रशिक्षण दिया गया है। टीपीडीडीएल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय बंगा और मुख्य वित्त अधिकारी एम शेनबागम ने केंद्र का उद्घाटन किया।

जामिया के ''चाइल्ड गाइडेंस सेंटर' को पूर्व छात्रों ने दिया पांच लाख का चंदा

नई दिल्ली। अलुम्नाई एसोसिएशन ऑफ़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया (आजमी) और ग्लोबल जामिया अलुम्नाई नेटवर्क (जीजान) के बैनर तले जामिया में दूसरे अलुम्नाई डे और जौहर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। अलुम्नाई मीट में करीब दो हज़ार पूर्व छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें देश के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, बहरीन, क़तर समेत कई और दूसरे मुल्कों से आए पूर्व छात्र भी शामिल थे। इस आयोजन में जामिया मिल्लिया के कैंपस में एक गैर सरकारी संस्था की ओर से चलाए जा रहे स्कूल ''चाइल्ड गाइडेंस सेंटर' को विविद्यालय के पूर्व छात्रों ने करीब 5 लाख रपए का चंदा दिया। स्कूल मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए चलाया जा रहा है और आर्थिक तंगी से गुज़र रहा है। कुलपति प्रो. शाहिद अशरफ मुख्य अतिथि और रजिस्ट्रार एपी सिद्दीकी (आईपीएस) गेस्ट ऑफ़ ऑनर थे। दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री कमाल अख्तर, आरजे नावेद, स्वामी चेतेश्वरानंद समेत पूर्व छात्र इस आयोजन में शामिल हुए।

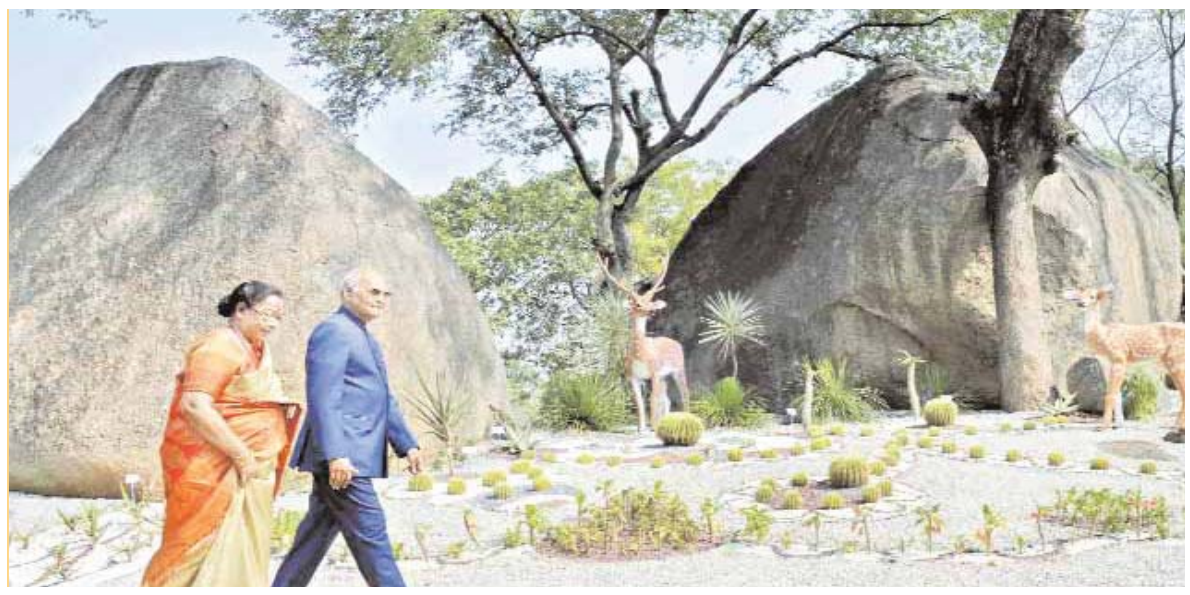

किंदराबाद : ''राष्ट्रपति निलयम' स्थित रॉक गार्डन में सोमवार को पत्नी सविता

»»» मोदी ने अटल की याद में सिक्का जारी किया

सत्ता है ऑक्सीजन, हट जाए तो तड़पने लगते हैं

कांग्रेस पर साधा निशाना नवीन को भी लिया निशाने पर

भुवनेश्वर एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा में नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल (बीजद) सरकार पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में ''भ्रष्टाचार का दानव' मजबूत हुआ है। मोदी यहां भाजपा की एक रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजद सरकार पर तंज कसते हुए पूछा, दानव (भ्रष्टाचार के) को कौन बढ़ा रहा है? पीसी (प्रतिशत कमीशन) संस्कृति .. में भ्रष्टाचार का दानव मजबूत हुआ है। ओडिशा के विकास की सच्चाई छिपी हुई नहीं है। किसान, महिलाएं अपनी आवाज उठा रही हैं।

ओडिशा में परियोजनाओं की शुरुआत

1660 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आईआईटी भुवनेश्वर के नए कैंपस का शुभारंभ किया

14,523 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की।

पाइका विद्रोह की याद में टिकट, सिक्का जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 1817 के पाइका विद्रोह की याद में सोमवार को एक टिकट और एक सिक्का जारी किया। पाइका विद्रोह को कई लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई मानते हैं। अंग्रेजों द्वारा राजस्व पणाली में किए गए फेरबदल ने लोगों में आक्रोश भर दिया, जिसके बाद ओडिशा के किसान समुदाय ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा, ''कुछ लोगों के लिए सत्ता ऑक्सीजन है वो इसके बिना जी नहीं सकते लेकिन वाजपेयी जी ने लंबे समय तक विपक्ष में रहकर राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन किया।' पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 94वीं जयंती की पूर्व संध्या पर उनकी स्मृति में 100 रपए का सिक्का जारी करते हुए पीएम मोदी ने यह बात कही। उन्होंने इस मौके पर आगे कहा, ''अटल जी लोकतंत्र की सर्वोच्चता चाहते थे। उन्होंने जनसंघ बनाया लेकिन जब लोकतंत्र को बचाने का समय आया तो वाजपेयी और अन्य नेता जनता पार्टी में शामिल हो गए। जब सत्ता में रहने अथवा विचारधारा पर अडिग रहने का प्रश्न आया तो वाजपेयी जी ने जनता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बनाई।' इससे वाजपेयी के भारतीय लोगों और जनसंघ की विचारधारा में विास का पता चलता है जब उन्होंने भाजपा के गठन के बाद कहा था, ''अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा'।

वक्ता के तौर पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। उन्हें हमेशा राष्ट्र के श्रेष्ठ वक्ताओं में गिना जाता रहेगा। इस समारोह में लंबे समय तक वाजपेयी के सहयोगी रहे वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, वित्त मंत्री अरुण जेटली और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह उपस्थित थे।उन्होंने कहा कि सिद्धांतों और कार्यकर्ता के बल पर अटल जी ने इतना बड़ा राजनीतिक संगठन खड़ा कर दिया और काफी कम समय में देशभर में उसका विस्तार भी किया। उन्होंने कहा कि अटल जी के बोलने का मतलब देश का बोलना और सुनने का मतलब देश को सुनना था।

अटल जी ने लोभ और स्वार्थ की बजाय देश और लोकतंत्र को सवरेपरि रखा और उसे ही चुना। उन्होंने कहा ''''मन अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि अटल जी अब हमारे साथ नहीं हैं। वह समाज के सभी वगरे के प्रति प्रेम रखने वाले और सम्मानित व्यक्ति थे। एक वक्ता के रूप में वह अद्वितीय थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को सार्वजनिक जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, राष्ट्र जीवन के लिए समर्पण भाव की खातिर हमेशा-हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। वाजपेयी ने अपने सार्वजनिक जीवन का लम्बा समय राष्ट्र हित से जुड़े विषयों को उठाने में लगाया।

सुनंदा मामले में सुब्रह्मण्यम की अर्जी पर फैसला अब 8 को

नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की अर्जी पर अदालत अब 8 जनवरी को फैसला सुनाएगा। स्वामी ने अदालत से सहयोग करने एवं पुलिस की खुद की जांच रिपोर्ट पेश करने की मांग की है। अदालत इस मामले में आरोपी बनाये गए कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को मुकदमे से संबंधित सभी दस्तावेज मुहैया कराने के मामले में भी सुनवाई करेगी। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत ने इस मामले में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के एक अधिकारी को भी तलब किया है क्योंकि कई इलेक्ट्रानिक दस्तावेज खुल नहीं रहे हैं। इसकी शिकायत थरूर के अधिवक्ता ने अदालत से की थी। थरूर की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत से कहा था कि वे पुलिस की भेजी रिपोर्ट नहीं खोल पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के दिए इलेक्ट्रानिक साक्ष्य में विसंगतियां है। साक्ष्य की सूची में दर्ज दस्तावेज उन्हें नहीं मिले हैं या वे उन्हें नहीं खोल पा रहे हैं। अदालत ने तब पुलिस से सभी दस्तावेज मुहैया कराने को कहा और सीएसएफएल के अधिकारी को तलब कर लिया। स्वामी ने अदालत से कहा था कि उन्हें इस मामले में अदालत को सहयोग करने दिया जाय।

कमलनाथ के कैबिनेट में 2 महिलाओं समेत 28 मंत्रियों ने ली शपथ, दिग्विजय सिंह के बेटे भी शामिल

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन आयोजित एक गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार के 28 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इसमें दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में डॉ गोविंद सिंह, बाला बच्चन, सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, डॉ विजयलक्ष्मी साधौ, सचिन यादव, तरूण भनोत, सुरेंद्र सिंह बघेल, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, पी सी शर्मा, उमंग सिंघार, हर्ष यादव, जयवर्धन सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। राज्यपाल ने प्रभुराम चौधरी, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पांसे, गोविंद सिंह राजपूत, श्रीमती इमरती देवी, आरिफ अकील, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, ओमकार सिंह मरकाम, प्रदीप जायसवाल, लाखन सिंह यादव और तुलसीराम सिलावट को भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई। कमलनाथ ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आज कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। इस प्रकार अब प्रदेश में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 29 मंत्री हो गए हैं।

यूपी : लखनऊ स्थित लोकभवन में लगेगी अटल जी की 25 फुट ऊंची प्रतिमा

लखनऊ, एजेंसी। लखनऊ स्थित लोकभवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। यह ऐलान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वाजपेयी की 95वीं जयंती के मौके पर आयोजित 'महानायक अटल' विषयक परिचर्चा में किया। प्रतिमा की ऊंचाई 25 फुट होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तर प्रदेश से अटूट संबंध था। सार्वजनिक जीवन की शुरूआत उन्होंने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद से की तथा पांच बार लखनऊ से सांसद रहे। सीएम ने आगे कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन के आधारस्तंभ थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी से उन्होंने राजनीति के गुर सीखे तथा राजनीति में भरोसे के प्रतीक बने।

सीएम योगी ने कहा कि वाजपेयी को अनेक पदों पर रहते हुए जो सम्मान प्राप्त हुआ, वह अद्भुत है। वह लंबे समय तक लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में काम करते रहे जो प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने बताया कि वाजपेयी की स्मृति में कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। ' 'लोक भवन में उनकी 25 फुट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जायेगी।'' गौरतलब है कि राजभवन की ओर से जारी बयान में पहले वाजपेयी की प्रतिमा की ऊंचाई 25 मीटर बताई गई थी। लेकिन बाद में एक संशोधित बयान जारी हुआ जिसमें प्रतिमा की ऊंचाई 25 फुट बतायी गई। इस मौके पर राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु ईसा मसीह, महामना मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि एक ही है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे सभी महान व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा प्रदेश की जनता की ओर से नमन करता हूं। राम नाईक ने आगे कहा कि वाजपेयी राजनीति के महानायक तथा देश के सर्वमान्य नेता थे। दल के लोग उनकी प्रशंसा करें तो स्वाभाविक है पर अटल जी की स्तुति विपक्षी दल के नेता भी करते हैं। परिचर्चा से पूर्व नाईक, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, दीक्षित, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, महापौर संयुक्ता भाटिया ने लोक भवन के प्रांगण में लगे दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

किसानों की कर्ज माफी के बाद अब बेरोजगार युवाओं के लिए भी कदम उठाएगी सरकार : सचिन पायलट

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा के बाद राज्य सरकार जल्द ही युवाओं की रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा है कि किसानों के मुद्दे और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना राज्य की कांग्रेस सरकार के एजेंडे में प्राथमिकता में रहेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है और सरकार घोषणा पत्र के अनुरूप अपने कार्य को मूर्त रूप देना शुरू करेगी। पायलट ने मंगलवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि हमने पहले ही दिन से किसानों की कर्जमाफी के साथ अपना काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि संकट सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर है और बहुत जल्द सरकार द्वारा किसान समुदाय के लिए 'इको सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए त्वरित और ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खेती एक लाभदायक उद्यम बन जाए। उन्होंने कहा कि हम शीघ्र ही युवाओं के लिये प्राथमिकता के आधार पर रोजगार पैदा करने का काम शुरू करेंगे। सरकार किसानों के मुद्दे और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सैद्धांतिक रूप से अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है क्योंकि राजस्थान को ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो दोनों मोर्चों पर अपने वादो को पूरा कर सके। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ने अपना घोषणा पत्र मुख्य सचिव को दे दिया है और सरकार द्वारा कार्य करने के लिये इसे एक आधिकारिक दस्तावेज बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिन योजनाओं के वादे किये है उन्हें शीघ्र ही आगे बढाया जायेगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ ग्रहण करने के दो दिन बाद 19 दिसम्बर को किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। राजस्थान की नवनिर्वाचित अशोक गहलोत सरकार ने पिछले सप्ताह किसानों का सहकारी बैंक से लिया गया अल्पकालीन कर्ज और दो लाख रूपये तक के कृषि रिण माफ करने की घोषणा की थी। इससे सरकारी खजाने पर लगभग 18000 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। जब उनसे रिण माफी से सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को जुटाने के बारे में पूछा गया तो पायलट ने बताया कि सरकार इस तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होने पर संसाधन जुटाना बहुत बडा काम नहीं है। पूर्व संप्रग सरकार ने 72000 करोड रूपये के किसानों के कर्ज माफ किये थे, इसलिये हम इसे कर सकते है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिये पूरी तरह सक्षम है। पायलट, जो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी है, ने कहा कि किसानों की रिण माफी से ना केवल किसानों की मदद हुई है बल्कि इससे किसानों के अलावा अन्य लोगों को भी संदेश पहुंचा है कि नई सरकार लोगों को सुनने को तैयार है और उनकी समस्याओं का समाधान करने को तैयार है। इसी तरह युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के वास्ते पायलट ने कहा कि इस तरह का तंत्र विकसित किया जायेगा जो लगातार नौकरियां पैदा करेगा और भर्तियां निकाली जायेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता को हमने अपनी प्रतिबद्वता दिखाई है। किसानों का कर्जा माफी पहला निर्णय था और अन्य निर्णय इसके बाद लिये जायेंगे। किसान और युवा भाजपा सरकार की कभी प्राथमिकता नहीं रहे। सोमवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पायलट ने कहा कि यह विस्तार युवा और अनुभवी नेताओं के बीच एक उर्जावान संतुलित मंत्रिमंडल है। उन्होंने कहा कि हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, हमारा मंत्रिमंडल पूरी तरह से उर्जावान है, सरकार चुनौतियों का सामना करने के लिये हर तरीके से तैयार है और जनता की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करेगी।

अल-अजीजिया स्टील मामले में फंसे, 15 लाख पोंड जुर्माना ठोका

भ्रष्टाचार में सात वर्ष के लिए जेल भेजे गए नवाज शरीफ

एनएसी ने संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया

इस्लामाबाद ■ एजेंसी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जवाबदेह अदालत ने अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार के मामले में सात साल जेल की सजा सुनाई है। वहीं उन्हें फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट मामले में बरी कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के मुखिया को जल्द ही अदियाला जेल ले जाया जाएगा। नवाज के अदालत परिसर पहुंचने के कुछ देर बाद ही यह सजा सुनाई गई।

जैसे ही नवाज इस्लामाबाद स्थित फेडरल ज्यूडियल कॉम्पलेक्स में पहुंचे वहां मौजूद पीएमएल-एन के समर्थकों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और जबरन अदालत के अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस ने

एक मामले में मिली राहत

प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले फेंके और उनपर लाठियां भांजी। उम्मीद थी कि नवाज को सजा सुबह 9-10 बजे के बीच सुनाई जाएगी। हालांकि अज्ञात कारणों की वजह से सजा सुनाने में देरी हुई। सूत्रों का कहना है कि लगभग 2 बजे शरीफ को अदालत ने सजा सुनाई।

सोमवार को पाकिस्तान की उच्चतम न्यायालय ने शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के बचे हुए दो मामलों में सजा सुनाई। शरीफ फैसले से एक दिन पहले रविवार को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे थे। डॉन के मुताबिक जवाबदेही अदालत में लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी को भी सोमवार की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाय उनके जिनके पास रजिस्ट्रार की अनुमति है। अदालत परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

अदालत के बाहर और वहां तक जाने वाली सड़कों पर पुलिस एवं रेंजर्स के दस्तों की तैनाती की गई थी। इससे पहले जवाबदेही अदालत ने शरीफ को अगस्त 2017 में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी ठहराया था। पिछले सप्ताह जस्टिस ने शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने और दस्तावेज दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था।

नवाज शरीफ की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया गया

पाक की राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत ने अपने संक्षिप्त फैसले में कहा कि अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ ठोस सबूत थे। इस मामले में बुधवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मीडिया में आई शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार नवाज शरीफ पर ढाई करोड़ डालर और 15 लाख पौंड का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही नवाज शरीफ की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया गया है। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट मामले में अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ को सजा दिए जाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए इस मुकदमे में उन्हें बरी किया जाता है। फैसला सुनाये जाने के बाद नवाज शरीफ को अदालत परिसर में ही हिरासत में ले गया। उम्मीद है कि उन्हें जेल ले जाया जायेगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया कि उन्हें अदियाला जेल की बजाय लाहौर की कोट लखपत जेल भेजा जाये जिसकी अदालत ने मंजूरी दे दी।

संपादकीय

कितना घिरेगी मोदी सरकार

केंद्र में सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे-ऐसे फैसले लिए कि लोगों ने कहना शुरु कर दिया कि यह भाजपा कम और कांग्रेस-2 वाली सरकार ज्यादा नजर आ रही है। आरोप यह था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्यों और योजनाओं को आनन-फानन में पूरा करने या फिर उन्हें लागू कर आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से किया। यूपीए सरकार में जिन योजनाओं और फैसलों का विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने जमकर विरोध किया था उन्हें भी मोदी सरकार ने प्रमुखता के साथ लागू किया और बतला दिया कि उसका विरोध राजनीतिक दिखावा था, ठीक वैसे ही जैसे कि आमचुनाव के दौरान जनता से किए गए भाजपा के वादे चुनाव जीतने के बाद महज चुनावी जुमले साबित हुए। यह आखिर कौन नहीं जानता है कि आधार कार्ड तो कांग्रेस अपने यूपीए शासनकाल में लेकर आने वाली थी, लेकिन तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने ही इसका खुलकर न सिर्फ विरोध किया था बल्कि आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया था कि इसके जरिए यह सरकार करोड़ों का घपला करने जा रही है और लोगों की निजता का सवाल भी तब उठाया गया था।

बहरहाल रुकावटों के चलते क्रमबद्ध सुरक्षात्मक तौर पर एक अच्छी योजना को लागू करने से मनमोहन सरकार रह गई थी और इसका खामियाजा अब देश की जनता को तरह-तरह से भुगतना पड़ रहा है। इसे लेकर लोगों ने निजता का सवाल भी उठाया और अनेक याचिकाएं अदालत में लगाई गईं, लेकिन जो होना था सो हुआ और खबरें आती रहीं कि आधार का डाटा चोरी हो गया, कुछ ने कहा कि डाटा करोड़ों में बेंच दिया गया तो कुछ ने कहा इसके जरिए सरकार जनता को अपनी मुट्ठी में रखने का प्रयास कर रही है। बहरहाल अदालत में मामला होने के कारण किसी ने कुछ भी इस पर बोलना उचित नहीं समझा। यह जरुर देखने में आया कि मोदी सरकार ने अपने इरादों को पूरा करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी। पूर्ण बहुमत वाली सरकार होने के चलते वह तो हवा में उड़ने के लिए पूरी मशक्कत करती देखी गई और इस कारनामें को करने में वो कामयाब भी रही, लेकिन अफसोस कि उसे इससे जिन परिणामों की उम्मीद थी वो उसे हासिल होते नहीं दिखे। कुल मिलाकर सरकार की चाल उसी पर उल्टी पड़ती नजर आ गई।

बहरहाल अब यह बीती बात बिसार दे जैसी बात लग रही है क्योंकि अब तो मोदी सरकार के एक और आदेश को सामने रखकर बताया जा रहा है कि किसी भी कंप्यूटर का डेटा खंगाल कर सरकार निजता को पूरी तरह खत्म करने का इरादा कर चुकी है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसके तहत किसी भी कंप्यूटर का डेटा सरकार जब चाहेगी तब खंगाल सकेगी। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने कंप्यूटर के डेटा की जांच के लिए दस केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारों को बढ़ा दिया है। इस आधार पर अब ये जांच एजेंसियां किसी भी कंप्यूटर में मौजूद डेटा की जांच कर सकेंगी। यह हैरान करने वाली बात है कि कंप्यूटर युग की शुरुआत से लेकर आज तक किसी के दिमाग में यह बात कभी नहीं आई होगी कि जिसे वो अपनी पर्सनल डायरी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सरकार के सामने खुली किताब साबित हो सकती है। इसलिए इसे सीधे तौर पर निजता पर हमला करार दिया जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जबकि एजेंसियों को कंप्यूटर का डाटा खंगालने की इजाजत दे दी गई है।

केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने इससे संबंधित यहां आदेश जारी किया वहां विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोलना शुरु कर दिया। निजता या मौलिक अधिकारों के खिलाफ यह इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक भी यह ठीक नहीं बैठता है। इसी बात को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भी यह निजता आपका मौलिक अधिकार है। निजता के अधिकार पर यह आदेश चोट पहुंचाता है। एक प्रकार से इस आदेश से मोदी सरकार देश के प्रत्येक नागरिक की पूरी जानकारी को देखने की अनुमति देने जैसा काम कर रही है। इससे प्रजातंत्र भी खतरे में आता दिख रहा है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार से बौखलाई मोदी सरकार अब लोगों की जासूसी उनके कंप्यूटर में मौजूद डाटा को खंगालकर करना चाहती है, इसलिए इसका विरोध तो होगा और उस स्तर तक होगा जब तक कि इस पर दोबारा विचार करने का कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। वैसे देखा जाए तो पूर्ण बहुमत वाली सरकार को ऐसे विरोधों से कोई फर्क फिलहाल पड़ता दिख नहीं रहा है, इसलिए चिंता की भी बात नहीं है, लेकिन जब 2019 आम चुनाव में भाजपा वोट मांगने मतदाता के द्वार जाएगी तब जरुर फर्क पड़ेगा। तब संभव है कि खामोश मतदाता मतदान के जरिए मौजूदा सरकार को निजता के सवाल पर घेर ले, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी।

@डॉ हिदायत अहमद खान

बच्चा जमूरा

प्रस्ताव पास कराएगा

❑ ***बच्चा जमूरे घूम जा।***
✡ घूम गया।
❑ ***जो पूछूंगा सच-सच बताओगे?***
✡ सच-सच बताऊंगा।
❑ ***आम आदमी पार्टी के नेता बार-बार यह दावा क्यों कर रहे हैं कि विधानसभा में राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की मांग का प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ?***
✡ दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर नियमों-कायदों को तोड़ते नजर आते हैं और इस बार भी यही हुआ है। हैरानी की बात यह है कि वे अपने झूठ को सच साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। सभी देख रहे हैं कि विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ और अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि प्रस्ताव पारित हुआ लेकिन अब वह कह रहे हैं कि प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।
❑ ***लेकिन यह कैसे हो सकता है!***
✡ यही तो हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सारे नेता कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव जरनैल सिंह ने पढ़ा, वह मूल प्रस्ताव नहीं था क्योंकि वह प्रस्ताव तो सोमनाथ भारती ने संशोधित कर दिया था और उस पर अपने हाथ से लिख दिया था। हैरानी की बात यह है कि पार्टी की ही एक विधायक अलका लांबा ने जो प्रस्ताव सोशल मीडिया पर डाला, उसमें राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का जिक्र साफ-साफ है। इसलिए यह कैसे कहा जा सकता है कि प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था। यही नहीं, जिस मेंबर ने प्रस्ताव पढ़ा, वही प्रस्ताव का पेश करने वाला है। उसने संशोधन कहकर नहीं पढ़ा और न ही अध्यक्ष ने उन्हें टोका कि आप यह क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपको यह पेश करना है तो फिर संशोधन के रूप में पेश कीजिए, जैसा कि अब आप आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। उन्होंने अपना प्रस्ताव पढ़ा और अध्यक्ष ने अति उत्साह में आकर कहा कि यह तो बहुत बड़ी बात है और हमें खड़े होकर यह प्रस्ताव पास करना चाहिए और फिर उन्होंने बाकायदा घोषणा भी की कि प्रस्ताव पास हो गया है। अब अगर वह कहते हैं कि प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो फिर खुद ही अपने आपको धोखा दे रहे हैं।
❑ ***लेकिन अब तो अध्यक्ष ने माना है कि मुझे उस सदस्य को टोकना चाहिए था?***
✡ यही तो अध्यक्ष की ड्यूटी थी कि सदन में इस तरह का कोई प्रस्ताव न आ जाए कि जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे। राजीव गांधी सिर्फ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं थे बल्कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। इसीलिए उन्हें शहीद मानते हुए भारत रत्न दिया गया। आखिर दिल्ली सरकार एक दिवंगत नेता के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव कैसे पास कर सकती है लेकिन अध्यक्ष की लापरवाही या फिर यह कहिए कि कोई नियम पर न चलने की मंशा के कारण ही यह हालात पैदा हो गए कि उन्हें यह पता ही नहीं चला कि सदस्य ने ऐसा प्रस्ताव पेश कर दिया है और उन्होंने उसे पास करा दिया। अब कोई कुछ भी कहे, प्रस्ताव तो पास हो ही चुका है।

फरमाते हैं

- मौजूदा राजनीति का माहौल बहुत गड़बड़ाया हुआ है। जो लोग सत्ता में है वे देश में प्रजातंत्र को समाप्त करना चाहते है और उनकी हर हरकत प्रजातंत्र को डैमेज करती है। 3 हिंदी राज्यों में जनता ने शुभ संकेत दिए हैं।
  -यशवंत सिन्हा
  (बागी भाजपा नेता)
- दिल्ली में सीलिंग 22 दिसंबर, 2017 को शुरू हुई थी। शनिवार को इस सीलिंग रूपी दैत्य को एक साल पूरा हो गया। वर्ष 2017 से लेकर आज तक दिल्ली में हजारों लोग अपनी रोजी रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। उनमें न केवल व्यापारी बल्कि उनके यहां काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं।
  -बृजेश गोयल
  (आप नेता)
- कहते हैं शिक्षा से गरिमा मिलती है, लेकिन इन पशुवत हालातों में बच्चों के भविष्य की क्या उम्मीद। सरकार या तो विद्यार्थियों को दूर ले जाने का प्रबंध करे या स्कूलों को बच्चों के करीब खोले। शिक्षा वर्तमान सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय नहीं है, तभी तो उसने शिक्षा का बजट घटा दिया है।
  -अखिलेश यादव
  (सपा नेता)
- सिद्धांतों और कार्यकर्ता के बल पर अटलजी ने भाजपा जैसा बड़ा राजनीतिक संगठन खड़ा कर दिया और काफी कम समय में देशभर में उसका विस्तार भी किया।
  -नरेंद्र मोदी
  (प्रधानमंत्री)

आज भी न्याय की गुहार लगा रही भारतीय 'न्याय व्यवस्था'

एक तरफ देश इक्कीसवीं सदी की ओर दौड़ लगा रहा है वहीं दूसरी ओर करोड़ों की संख्या में पीड़ित जनता प्रतिदिन मुंसिफ न्यायालय से लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट तक न्याय पाने के लिये दौड़ लगा रही है। लेकिन उसे हर बार तारीख पर तारीख के दौर से गुजरना पड़ रहा है। जिससे सबको को न्याय देने वाली न्याय पालिका जजों के अभाव के चलते खुद न्याय पाने के लिये सिसक रही है। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो अथवा किसी भी राज्य में किसी भी दल की सरकार हो जनता के रहनुमा होने के लम्बे चैड़े दावे या वायदे करने में कभी भी पीछे नहीं रही हैं। प्रत्येक सरकार ने वोट की चाहत में दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े, गरीब, मजदूर, व्यापारियों, उद्योगपतियों के हितों के लिये तमाम योजनाओं के नाम पर लाखों-करोड़ों हजार की राशि तो पानी की तरह बहायी है। लेकिन न्याय व्यवस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया जाता रहा है। यही कारण है कि जैसे-जैसे देश की आबादी बढ़ती गई वैसे-वैसे जजों की संख्या बढ़ने के स्थान पर लगातार घटती चली गई। वहीं मुकदमों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी होती गई जो अब करीब 2.20 करोड़ तक पहुंच गई है। आज से करीब तीन दशक पूर्व वर्ष 1987 में गठित लॉ कमीशन ने न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों की संख्या को देखते हुए 10 लाख की आबादी पर जजों की संख्या 18 से बढ़ाकर 50 करने की सन्तुति की थी। लेकिन इस रिपोर्ट को केन्द्र सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जबकि इन तीन दशकों में जनसंख्या विकराल रूप धारण करती गई बल्कि न्यायालयों की संख्या में भी इजाफा होता रहा। लेकिन जजों की संख्या बढ़ने के स्थान पर अवकाश ग्रहण करने और उनकी नयी भर्ती न होने से जजों की सीटें लगातार खाली होती गईं और मुकद्मों का बोझ न्यायालयों में लगातार बढ़ता गया। पिछले दिनों सवोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर के भारतीय न्याय व्यवस्था की हालत को देखकर दिल्ली के विज्ञान भवन में उस समय आंसू छलक आये थे जब वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। लेकिन उसके बाद भी स्थिति में कहीं कोई सुधार होता नजर नहीं आया। हाल ही में लोकसभा में विधि एवं न्याय तथा इलैक्ट्रोनिक एवं सूचना तकनीक राज यमंत्री पीपी चैधरी ने बताया कि 30 जून 2016 तक सुप्रीम कोर्ट में 62,657 मामले लम्बित हैं। उच्च न्यायालयों में 477 पद न्यायाधीशों के खाली हैं जबकि 10 लाख की आबादी पर देश के न्यायालयों में 18 जज कार्यरत हैं। जबकि वर्ष 2012 में 17,715 की जजों की संख्या को 20,502 कर दिया गया है। इसी तरह उच्च न्यायालयों में 98 6 जजों की संख्या को जून 2014 में 1079 कर दिया गया। जिला एवं अधीनिस्थ न्यायालयों में 31 दिसम्बर 2015 तक 4432 पद खाली पड़े थे। उच्च न्यायालयों में 31 दिसम्बर 2015 तक 38,70,373 मामले लम्बित पड़े हुए थे। जिनमें सर्वाधिक 9,18,829 मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 18 जजों की तैनाती 10 लाख की आबादी पर होने का दावा किया गया। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पद्रेश में सर्वाधिक 51 लाख (23 प्रतिशत), महाराष्ट्र 29 लाख (13 प्रतिशत), गुजरात 22.5 लाख (11 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल 13 लाख (6 प्रतिशत) इसके अलावा पिछले 10 वर्षों से उ.प्र. में 6.5 लाख, गुजरात में 5.20 लाख, महाराष्ट्र में 2.5 लाख मामले लम्बित हैं। भारतीय न्यायव्यवस्था की बदतर स्थिति का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 20 लाख से अधिक मामले महिलाओं के लम्बित हैं। वहीं 3 प्रतिशत मुकदमे सीनियर सिटीजन (वृद्ध) के लम्बित हैं। जबकि 38.30 लाख मामले पिछले पांच वर्षों से लम्बित हैं जो कुल मुकदमों का 17.5 प्रतिशत है। उच्च न्यायालयों में करीब 400 (39 प्रतिशत) पद खाली पड़े हैं। जिसमें सबसे बदतर हालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की है जहां करीब 50

प्रतिशत जज ही तैनात हैं। देश के अन्य उच्च न्यायालयों की हालत की बात करें तो सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय को छोड़कर किसी भी राज्य में जजों की संख्या पूर्ण नहीं है। बिगड़ती न्याय व्यवस्था में सुधार के लिये लॉ कमीशन द्वारा वर्ष 2014 में 245वीं रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपी गई। जिसमें पुन: लाख की आबादी पर 50 जजों की सन्तुति की गई। बल्कि उच्च न्यायालयों में बैकलॉग को भरने के लिये अतिरिक्त जजों की तैनाती की भी सन्तुति की गई। लेकिन उक्त सन्तुति पर भी केन्द्र सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। देश में निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालय, सवोच्च न्यायालय तक फरियादियों की भीड़ नजर आती है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन हो या फिर दिल्ली का रेलवे स्टेशन हर जगह पीड़ितों का एक कारवां नजर आता है। जगह-जगह गरीब पीड़ित फरियादी रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्डों पर न्याय की उम्मीद में खुले आसमान के नीचे रात्रि को करवटें बदलते हुए नजर आयेंगे या फिर अन्य न्यायालयों से मिली अगली तारीख को लेकर भारतीय न्याय व्यवस्था को कोसते हुए अपने घरों को लौटते दिखाई देंगे। जबकि जमानत के इंतजार में लाखों कैदी न्यायालय के आदेश के इंतजार में पल-पल न्यायालयों की ओर टकटकी लगाते दिखाई दे जायेंगे। लेकिन उनकी तड़प उस समय गुस्से में तब्दील हो जाती है जब उन्हें मालूम होता है कि न्यायालय में आज जज ही नहीं बैठा है, वकीलों ने हड़ताल कर दी है। या फिर अगली तारीख पड़ गई है। न्यायालयों में तारीख पर तारीख का दौर कब खत्म होगा यह तो कहना मुश्किल है। लेकिन देश की जनता को न्याय देने वाली न्याय व्यवस्था ही अपने प्रति हो रहे अन्याय को देखकर सिसक रही है कि क्या देश के नेता और सरकार उसके साथ क्या कभी न्याय कर पायेंगे। **आलेख डॉ. नेहा नेमा मप्र**

'बाहरी' अब अन्तर्राष्ट्रीय महारोग?

@ओमप्रकाश मेहता

मालवी की एक कहावत है- 'घर का जोगी जोगड़ा, आनगांव का सिद्ध' अर्थात अपने क्षेत्रवासियों की खूबियों की अपने क्षेत्र में कद्र नहीं होती, जबकि बाहर के उस शख्स को सिद्ध पुरूष माना जाता है, जो स्थानीय से कई मामलों में निम्नस्तरीय होता है। आज इस उक्ति की याद इसलिए आई क्योंकि सारी दुनिया में आज 'बाहरी' अछूत माना जाने लगा है। अरे, अब तो यह 'बाहरी' मुद्दा लोगों को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा देता है, जिसका ज्वलंत उदाहरण अमेरिका है जहां मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सिर्फ 'बाहरी' के मुद्दे पर सताईस महीने पहले सत्ता हासिल कर ली थी। मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ, जब ट्रम्प ने अपने चुनावी भाषणों में भारत तथा अन्य कुछ देशों से अमेरिका नौकरी करने आने वाले युवाओं को वीज़ा रद्द कर स्थानीय युवाओं को नौकरियों में वरीयता देने की घोषणा की थी, ट्रम्प की यह चुनावी चाल काम कर गई और वे युवाओं का वोट पाकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए।

आज इसी रोग के वॉयरस से पूरा विश्व पीड़ित है, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसमें 'बाहरी वॉयरस' ने अपना असर न दिखाया हो? भारत में इसकी शुरूआत कुछ वर्षों पहले महाराष्ट्र से हुई थी, जहां के वजनदार नेता स्व. बाला साहब ठाकरे ने 'आमचा महाराष्ट्र' का नारा देकर उत्तरप्रदेश व बिहार के महाराष्ट्र में रोजगार पर लगे लोगों को महाराष्ट्र से बाहर करने का अभियान चलाया था।

अब तो यह 'बाहरी' मुद्दा लोगों को सत्ता के लसहासन तक पहुंचा देता है, जिसका ज्वलंत उदाहरण अमेरिका है जहां मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सिर्फ 'बाहरी' मुद्दे पर सताईस महीने पहले सत्ता हासिल कर ली थी।

अब उन्ही का अनुसरण उनके भतीजे राज ठाकरे व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कर रहे है, धीरे-धीरे यह रोग देश के अन्य प्रांतों में भी फैला और अब इसका असर मध्यप्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, नवागत मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के उस बयान के बाद जिसमें प्रदेश के उद्योगों में उत्तर प्रदेश व बिहार के युवाओं को रोजगार मिलने और प्रदेश के युवाओं को नौकरी न मिल पाने की शिकायत की गई है, अपने बयान के बाद तो कमलनाथ जी ने प्रदेश स्थित उद्योगों को निर्देश भी दे दिए है कि उद्योगों में सत्तर प्रतिशत रिक्त या नवसृजित पद मध्यप्रदेश के युवाओं से ही भरे जाए, शेष तीस प्रतिशत पर 'बाहरी' आ सकते है।

मध्यप्रदेश की सत्ता सम्हालने के तत्काल बाद जारी उनके इस बयान और उसके बाद जारी किए गए आदेश ने पूरे देश के गैर-कांग्रेसी दलों को कांग्रेस के खिलाफ एक मुद्दा दे दिया और बात कांग्रेस अध्यक्ष तक पहुंच गई। यद्यपि कमलनाथ ने सफाई दी कि यह मुद्दा कोई नया नहीं है, यह तो हर राज्य व हर देश में हो रहा है और उन्होंने कोई गलत बात नहीं कहीं, किंतु कमलनाथ जी के इस कथन के कई अर्थ निकाले गए, जिसका असर मोदी विरोधी बन रहे महागठबंधन पर भी पड़ा और उत्तरप्रदेश के नेता कांग्रेस से नाराज हो गए, जिनमें बसपा सुप्रीमों मायावती व सपाध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल है, बिहार के सत्तारूढ़ दल की नाराज हो गए। अब स्थिति यहां तक पहुंच गई कि कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ रही है। देश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सहित हर सियासी दल इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी चैकन्ना है, चूंकि सिर्फ एक सौ दिन बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले है और किसी भी दल के नेता के बयान को लेकर मतदाता का कोई वर्ग नाराज न हो, इसलिए हर राजनीतिक दल अपने नेताओं को तोल-मोल कर बोलने के निर्देश दे रहा है, खास कर भारतीय जनता पार्टी जिसके क्षेत्रीय नेता काफी वाचाल और अप्रिय भाषी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के मतदाताओं की नाराजगी को ध्यान में रखकर ही 2019 के महासंग्राम के लिए अपने दिशा-निर्देश जारी कर रहे है तथा सांसदों-विधायकों से भेंट करने का अभियान चलाने जा रहे है। देश के राजनीतिक दलों के इसी अभियान के दौरान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री का यूपी-बिहार विरोधी बयान आने से सियासी गलियारों में इतनी खलबली मची है। यद्यपि स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से कमलनाथ जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा लेकिन चुनावी दौर में ऐसे बयानों के विवाद के दायरे में आना स्वाभाविक है, अब जहां तक अमेरिका का सवाल है, वह 'बाहरी' के वीज़ा देना बंद कर सकता है, किंतु हम 'बाहरी' को रोकने के लिए आखिर क्या कर सकते है?

जीएसटी : दुरुस्त आयद

@डॉ. वेदप्रताप वैदिक

जीएसटी के मामले में मोदी सरकार की हालत वही हो गई थी, जो हालत किसी यजमान की हवन करते वक्त कभी-कभी हो जाती है याने हवन करते-करते हाथ जल जाते हैं। यह सारे देश के लिए एकरुप टैक्स इसलिए लाया गया था कि लोगों को अपने खरीदे हुए माल पर कम टैक्स देना पड़े और सरकारों और व्यापारियों का सिरदर्द भी कम हो जाए। लेकिन जब डॉक्टर ही भोंदू हो तो क्या करें? दवा ही दर्द बन जाती है। नोटबंदी के बाद जीएसटी ने इतना कीचड़ फैला दिया कि मोदी की नाव फंसने लगी। तीनों हिंदी राज्यों में हार का वह बड़ा कारण रहा है। जो व्यापारी समाज राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ और भाजपा के दानापानी का इंतजाम करता रहा है,

उसकी रीढ़ तोड़ने का काम नोटबंदी और जीएसटी ने कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि सरकार को अब अक्ल आ रही है। हिंदी प्रांतों के धक्के ने सर्वज्ञजी की नींद खोल दी है। अब जीएसटी कौंसिल ने 17 चीजों और 6 सेवाओं पर लगनेवाले टैक्सों को घटा दिया है। कुछ पर 28 प्रतिशत से 18 और कुछ पर 18 से 12 और कुछ पर शून्य टैक्स लगाया है। याने जैसा कि नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 99 प्रतिशत वस्तुएं अब सबसे ज्यादा टैक्स (28 प्रतिशत) से मुक्त कर दी गई हैं। इस कदम से सरकार को 5500 करोड़ रु. का घाटा होगा। अब भी 28 वस्तुएं ऐसी हैं, जिन पर टैक्स की दर 28 प्रतिशत हैं।

अगली बैठक में जीएसटी कौंसिल इनमें से कुछ चीजों पर टैक्स कम करेगी। बिना सोचे-समझे जल्दबाजी में उसने कई फैसले कर लिये थे, जिन्हें वह जाते-जाते ठीक करने की कोशिश करेगी। मुझे कुछ व्यापारियों ने बताया कि अभी तक कुछ चीजों पर इतने विचित्र ढंग से जीएसटी लगाया गया है कि हमको हमारे नेताओं पर हंसी आने लगे। जैसे छोले और भटूरे आप अलग-अलग खाएं तो आपको 18 प्रतिशत टैक्स देना होगा और साथ-साथ खाएं तो 12 प्रतिशत। कपड़ों में लगनेवाली झिप में चैन और स्लाइडर पर यह बात लागू होती है। फ्रोजन सब्जियां (बर्फ में जमी हुई) कौन लोग खाते हैं और कितने लोग खाते हैं? उन पर टैक्स माफ करने की तुक क्या है, समझ में नहीं आता। कुल मिलाकर सरकार के पास टैक्स की आमदनी धुआंधार हो रही है। इस आमदनी का सीधा फायदा गरीबों, ग्रामीणों और मजदूरों को मिले, यह जरुरी है। जीएसटी के हिसाब की प्रणाली को भी इतना सरल बनाया जाना चाहिए कि गांव के अनपढ़ व्यापारी को भी कोई दिक्कत न हो। यह भी अच्छा है कि विभिन्न राज्यों की टैक्स-प्रणालियों के विवादों को निपटाने के लिए एक केंद्रीकृत संस्था बनाई जा रही है। देर आयद, दुरुस्त आयद !

धर्म-चर्चा

भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य

भगवान भौतिक जगत के पालन व निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं हैं। हम एटलस (एक रोमन देवता) को कंधों पर गोला उठाये देखते हैं। वह अत्यन्त थका लगता है और इस विशाल पृथ्वीलोक को धारण किये रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए, जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किये हों। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, सारे लोक अन्तरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अन्तरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है किन्तु वे अन्तरिक्ष से पृथक स्थित हैं। भगवान कहते हैं, यद्यपि सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किन्तु भगवान रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूं। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है।

वैदिककोश निरुक्ति में कहा गया है- परमेश्वर शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं।

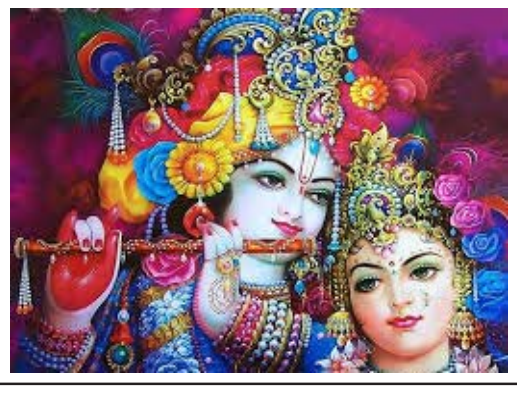

उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं, तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी-कभी जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते। किन्तु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं, तो सब इतनी पूर्णता से सम्पन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ! भगवान समझाते हैं-यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारणकर्ता हैं, किन्तु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है। वे हर वस्तु में उपस्थित हैं, किन्तु सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता कि वे साकार रूप में उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। इसे ही भगवान की योगशक्ति कहा गया है।

सार समाचार

चुनावों से पहले जारी हुआ सर्वे, बेंजामिन नेतन्याहू फिर बनेंगे इज़राइल के पीएम

यरुशलम। इज़राइल में मध्यावधि चुनाव की घोषणा होने के बाद मंगलवार को पहला जनमत सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आसानी से जीतने की संभावना जताई गई है। इजराइली दैनिक 'मारीव' में प्रकाशित 'पेनल्स पोलिटिक्स' के सर्वेक्षण में नेतन्याहू की सत्तारूढ़ लिकुद पार्टी को 120 संसदीय सीटों में से 30 सीटें मिल सकती हैं। उनकी पार्टी के पास अब भी इतनी ही सीटें हैं। पूर्व सैन्य प्रमुख बेन्नी गांत्ज की काल्पनिक पार्टी 13 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर आ सकती है। बहरहाल, अभी उनकी पार्टी का नाम का ऐलान नहीं हुआ है। उन्होंने अभी यह फैसला नहीं किया है कि वह चुनाव लड़ भी रहे हैं या नहीं। यह सर्वेक्षण 500 इज़राइली नागरिकों पर किया गया है। भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे नेतनयाहू ने सोमवार को अप्रैल में चुनाव कराने का ऐलान किया था। इस इज़राइली नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही हैं।

कांगो के विमान दुर्घटना में बाल-बाल बची यात्रियों की जान, 38 लोग घायल

बेनी। कांगो के बेनी में सोमवार को एक अंतोव परिवहन विमान के उतरने के लिए निर्धारित स्थान पर नहीं उतरने के कारण 38 लोग घायल हो गए। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि विमान में 68 यात्री और चालक दल के चार सदस्य सवार थे। हादसे में किसी की जान नहीं गई है। बेनी हवाईअड्डे के सुरक्षा प्रभारी लेफ्टिनेंट सोमवे मुलिम्बी ने कहा कि चालक दल के चार सदस्यों और कांगो की सेना के 34 सैनिकों सहित 38 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि घायलों में आठ सैनिकों की हालत गंभीर है। सेना के क्षेत्रीय प्रवक्ता कैप्टन मेक हाजुकई ने कहा कि विमान निर्धारित स्थल पर नहीं उतर पाया। उन्होंने हालांकि हादसे का और कोई ब्योरा नहीं दिया।

इस्लामिक स्टेट द्वारा मारे गए ईसाइयों के शव लीबिया में बरामद

त्रिपोली। इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूह द्वारा वर्ष 2015 में मौत के घाट उतारे गए 34 इथियोपियाई ईसाइयों के शव एक सामूहिक कब्र में मिले हैं। गृह मंत्रालय की एक शाखा ने सोमवार को यह जानकारी दी। आईएस के जिहादियों ने अप्रैल 2015 में एक वीडियो जारी किया था जिसमें वह कम से कम 28 लोगों की हत्या करते दिख रहे थे। इन्हें (मारे गए लोगों को) इथियोपियाई ईसाई बताया गया था।
अधिकारी ने सोमवार को बताया कि उनके शव सिर्त के पास से बरामद हुए हैं, जो कि दिसंबर 2016 से पहले तक जिहादियों का गढ़ था जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र समर्थित लीबिया सरकार के बलों ने आईएस को शहर से खदेड़ दिया था। उन्होंने कहा कि महाअभियोजक कार्यालय के अनुसार ये शव इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा मारे गए इथियोपियाई लोगों के हैं।

लाहौर: पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को जेल भेजा गया

लाहौर (एजेंसी)।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मंगलवार लाहौर की कोट लखपत जेल भेज दिया गया। एक दिन पहले ही देश की भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने उन्हें बहुचर्चित पनामा पेपर्स कांड से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में सात साल जेल की सजा सुनायी थी।

अदालत ने सोमवार को 69 वर्षीय शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी जबकि 'फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया था। इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत ने 'फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई शुरू की थी।

फैसले के बाद अदालत में ही शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया और रावलपिंडी की अडियाला जेल भेज दिया गया। अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें लाहौर में कोट लखपत जेल स्थानांतरित कर दिया।

शरीफ ने अपनी अर्जी में अदालत से अनुरोध किया था कि वह कोट लखपत जेल में अपनी सजा पूरी करना चाहते हैं क्योंकि उनके परिजन और उनके निजी डॉक्टर लाहौर में ही रहते हैं।

अपने नेता की एक झलक पाने के लिये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के समर्थक बड़ी संख्या में जेल के बाहर जमा हो गये। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण उन्हें जेल के करीब नहीं जाने दिया गया। पुलिस ने जेल पहुंचने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया।

जेल प्रशासन के अनुसार शरीफ को ऊंचे दर्जे वाली सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा, ऊंचे दर्जे के कैदियों को बिस्तर, पढ़ने के लिये मेज, दो कुर्सियां, एक टीवी सेट और अखबार दिया जाता है। शरीफ को उस बैरक में भेजा गया है जहां 1990 के दशक में भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को रखा गया था। कोट लखपत जेल पहुंचने पर डॉक्टरों ने शरीफ की जांच की और उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ पाया। सोमवार के फैसले पर टिप्पणी करते हुए शरीफ ने कहा कि उनकी सोच स्पष्ट है क्योंकि वह कभी भ्रष्टाचार के किसी मामले में शामिल नहीं रहे। उन्होंने कहा, मैं कभी भी अधिकार के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहा हूं। शरीफ के वकीलों ने कहा कि जवाबदेही अदालत के फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी जायेगी।

राष्ट्रपति एर्दोआन ने ट्रंप को तुर्की आने का दिया निमंत्रण: व्हाइट हाउस

वाशिंगटन (एजेंसी)।

तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रम्प को 2019 में तुर्की आने का निमंत्रण दिया है। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ''संभावित बैठक'' के लिए तैयार हैं हालांकि अभी कुछ तय नहीं हुआ है। ट्रम्प के सीरिया से अमेरिकी सैनिक वापस बुलाने के विवादस्पद निर्णय के कुछ दिन बाद यह निमंत्रण आया है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय युद्ध में

सहायता के लिए अमेरिकी सैनिक सीरिया में तैनात हैं।

व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव होगान गिड्ले ने कहा, 'राष्ट्रपति एर्दोआन ने राष्ट्रपति ट्रम्प को 2019 में तुर्की दौरे के लिए आमंत्रित किया है। अभी कुछ तय नहीं हुआ है लेकिन राष्ट्रपति भविष्य में ऐसी संभावित बैठकों के लिए तैयार हैं।' दूसरी ओर एर्दोआन के एक प्रवक्ता ने बताया कि ट्रम्प ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अमेरिकी मीडिया में पिछले कुछ दिनों से खबरें हैं कि ट्रम्प के सीरिया से सैनिक वापस बुलाने के निर्णय में एर्दोआन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ट्रंम्प ने हाल ही में कहा था कि आईएसआईएस को सीरिया से काफी हद तक खदेड़ दिया गया है और बाकी बचे आईएसआईएस लड़ाकों से तुर्की निपट सकता है।

हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्यूबला की गवर्नर, उनके पति पूर्व गवर्नर की मौत

मेक्सिको सिटी (एजेंसी)।

मेक्सिको में क्रिसमस से एक दिन पहले हुई एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्यूबला प्रांत की गवर्नर मैर्था एरिका अलोंसो और उनके पति पूर्व गवर्नर राफेल मोरेनो वैले की मौत हो गई। मोरेनो वैले वर्तमान में संघीय सीनेटर थे। राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडर ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और ट्वीट कर मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, 'मैं हादसे के कारणों की जांच और सच सामने लाने की प्रतिबद्धता जताता हूं।'

हादसे में हेलीकॉप्टर के दो पायलटों और सीनेटर के एक सहायक की भी मौत हो गई। हादसे में मारे गए दंपती की पार्टी नेशनल एक्शन पार्टी के अध्यक्ष मार्को कोर्टेस ने ट्वीट कर घटना पर दुख व्यक्त किया है। अलोंसो ने अभी 14 दिसंबर को ही गवर्नर पद की शपथ ली थी।

जुलाई में हुए चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। चुनाव परिणाम पर विवाद के बाद चुनाव प्राधिकरण ने उनकी जीत को प्रमाणित किया था। वह प्यूबला के गवर्नर पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थीं। उनके पति मोरेनो वैले वर्ष 2011 से 2017 तक मध्य राज्य प्यूबला के गवर्नर थे। स्थानीय संविधान के अनुसार अब अलोंसो की जगह एक अंतरिम गवर्नर की नियुक्ति होगी और तीन से पांच महीने के भीतर गवर्नर पद के लिए चुनाव कराना आवश्यक होगा।

पता चल गया सेंटा क्लॉज का पता, आप भी जानिए और सबको बताइए

नई दिल्ली (एजेंसी)।

दुनियाभर में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है. इस मौके पर हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि सेंटा क्लॉज आएंगे और उसे गिफ्ट देंगे. क्रिसमस पर कई बच्चों के घर पर या बिस्तर पर सेंटा क्लॉज गिफ्ट रखकर गए होंगे. बच्चे घर में सभी से पूछ रहे होंगे कि आखिर सेंटा क्लॉज कौन हैं और कहां से आते हैं. मां-पिता या घर के दूसरे बड़े लोग बच्चों को समझाने की कोशिश कर रह होंगे. ऐसे में हम आपको सेंटा क्लॉज का पता बता रहे हैं.

माना जाता है कि 300 ईसा पूर्व तुर्की के मायरा शहर में सेंट निकोलस नाम के शख्स रहते थे. वह काफी अमीर थे. उन्हें लोगों की मदद करना पसंद था. वे चाहते थे कि दुनिया में किसी भी इंसान के जीवन में कोई कष्ट ना हो. वह हमेशा खुश रहे. खासकर बच्चे जब उदास होते तो वह काफी परेशान हो जाया करते थे. इसी वजह से सेंट निकोलस एक खास किस्म की ड्रेस पहनकर बच्चों के पास जाते और उन्हें तोहफे देते. मान्यता है कि जीसस की मौत के करीब 280 साल पहले सेंट निकोलस का जन्म हुआ था.

सेंट निकोलस 17 साल की उम्र में ही पादरी बन गए थे. जीवनभर सेंट निकोलस आधी रात को बच्चों को गिफ्ट पहुंचाते रहे. उनकी मौत के बाद चर्च से जुड़े लोगों ने सेंट निकोलस की इस अच्छी आदत को जारी रखा. चर्च से जुड़े कर्मचारी गरीबों और बच्चों को छिपकर खाने-पीने की चीजें और उपहार पहुंचाया करते थे. तब से यह परंपरा दुनियाभर में चल रही है. घर के बड़े बुजुर्ग रात में बच्चों के लिए गिफ्ट रख देते हैं. बच्चे समझते हैं कि सेंटा क्लॉज आए थे.

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविदों ने हड्डी के इस टुकड़े को एक सूक्ष्म-नमूने पर रेडियोकार्बन परीक्षण के बाद कहा है कि यह हड्डी 1087 ईसवी की है. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस समय तक संत निकोलस का मृत्यु हो गई थी.

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी एक एक बयान में केबेल कॉलेज के एडवांस्ड स्टडीज सेंटर में ऑक्सफोर्ड अवशेष समूह के निदेशक प्रोफेसर टॉम हाम का कहना है कि यह हड्डी का टुकड़ा सेंट निकोलस का अवशेष हो सकता है.

क्रिसमस जीसस के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है इसलिए इस दिन उपहार देने की परंपरा है. इसी वजह से सेंटा क्लॉज की वह अच्छी आदत आज दुनियाभर में लोकप्रिय है. अब तो आप सेंटा क्लॉज का पता जान चुके हैं. अब आप यहां से जुटाई गई सेंटा से जुड़ी जानकारी लोगों को बता सकते हैं. खासकर बच्चों को बता सकते हैं कि सेंटा कौन हैं और कहां से आते हैं.

डोकलाम से वुहान तक, 2018 में भारत-चीन संबंधों में जबर्दस्त बदलाव दिखा

बीजिंग (एजेंसी)।

भारत-चीन सबंधों में 2018 में सद्भाव देखने को मिला। जहां 2017 में दोनों के बीच डोकलाम में एक बड़ा सैन्य गतिरोध उत्पन्न हो गया था, इस साल दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच पहली अनौपचारिक शिखर बैठक हुई और इससे एशिया के दो बड़े देशों के बीच तनाव कम करने में मदद मिली। वर्ष 2017 में भारत-चीन के द्विपक्षीय संबंधों में 60 अरब डालर वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपेक) के साथ ही डोकलाम में दोनों देशों की सेनाओं के 73 दिन तक आमने सामने डटे रहने के चलते कड़वाहट आ गई थी। सीपेक 'बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव' (बीआरआई) का एक हिस्सा है जो चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्देश्य विदेश में चीन का प्रभाव बढ़ाना है।

सीपेक और डोकलाम को लेकर गतिरोध ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को वुहान में शिखर बैठक में दोनों देशों के संबंधों में शांतिपूर्ण विकास की संभावना का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। दोनों नेताओं के रणनीतिक दिशानिर्देश में भारत और चीन ने 2018 में संयुक्त सैन्य अभ्यास बहाल किया। यह दोनों देशों के बीच 18 महीने पहले डोकलाम में सैन्य गतिरोध के बाद पहला ऐसा अभ्यास था। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत-चीन संबंधों में इस वर्ष आये बदलावों की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान परिवर्तनशाली अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में चीन-भारत संबंधों का सार्थक विकास दोनों देशों के मूलभूत हितों के अनुरूप है।

चीन के विदेश मंत्रालय ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, '2019 में चीन भारत के साथ राजनीतिक परस्पर विश्वास बढ़ाने, आदान-प्रदान और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, मतभेदों को सही तरीके से सुलझाने, दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति के अनुरूप चीन-भारत संबंधों के तेज, बेहतर और अधिक स्थिर विकास को बढ़ावा देने के वास्ते काम करने को तैयार है।' बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव से चीन से लगे दक्षिण एशियाई पड़ोस में भारत का प्रभाव कम होने का खतरा उत्पन्न हुआ क्योंकि चीन ऋण कूटनीति के आरोपों के बीच छोटे देशों को आधारभूत परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर का ऋण दे रहा है। इस बीच, सीपेक चीन-भारत संबंधों में सबसे बड़े व्यवधान के तौर पर उभरा है। भारत की इस आपत्ति के बावजूद कि सीपेक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, चीन सीपेक पर आगे बढ़ा।

भारत ने इसको देखते हुए पिछले वर्ष राष्ट्रपति शी की ओर से आयोजित बीआरआई फोरम का बहिष्कार किया। चीन ने इसके साथ ही परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने और जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के भारत के प्रयास में बाधा उत्पन्न की जिससे दोनों देशों के संबंधों में दरार और बढ़ गई। वर्ष के बड़े हिस्से के दौरान चीन में भारत के राजदूत रहे गौतम बम्बावाले ने कहा, '2018 एक ऐसा वर्ष था जिस दौरान भारत..चीन संबंध डोकलाम से वुहान और उसके आगे बढ़े।' बम्बावाले ने पहले अनौपचारिक सम्मेलन के लिए चीन के अधिकारियों के साथ नजदीकी रूप में संवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

बम्बावाले 30 नवम्बर को सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने पीटीआई से एक ईमेल जवाब में कहा, 'ऐसा करने के लिए दोनों देशों और उनके नेतृत्व को आत्मनिरीक्षण करना पड़ा और स्वतंत्र रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई अनौपचारिक शिखर बैठक दोनों नेताओं को रणनीतिक संवाद का एक मौका प्रदान करेगी। वुहान में उनकी बातचीत से संबंधों में सुधार का एक माहौल बना।' उन्होंने कहा, 'इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संवाद देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी इस वर्ष चार बार मिले। जिस पर ध्यान नहीं दिया गया वह यह

है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और चीन के रक्षा मंत्री वेई फंगह ने भी इस वर्ष तीन बार मुलाकात की। हमारे विदेश मंत्रियों ने भी कई बार मुलाकात की। चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री की इस वर्ष की भारत यात्रा भी एक महत्वपूर्ण घटना थी।'

बम्बावाले ने चेंगदू में भारत और चीन के बीच 'हैंड इन हैंड' सैन्य अभ्यास बहाली और रक्षा संवाद बहाली का उल्लेख करते हुए कहा कि द्विपक्षीय सैन्य संबंधों का विकास ''इस वर्ष भारत.चीन संवाद में सबसे महत्वपूर्ण रहा।'' 'हैंड इन हैंड' और रक्षा संवाद दोनों डोकलाम गतिरोध के चलते एक वर्ष के अंतराल पर हुए। दोनों देशों ने गत नवम्बर में 21वें दौर की सीमा वार्ता की जिसमें उन्होंने सीमा मुद्दे के हल के लिए संवाद प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

क्रांति समय

स्वच्छ भारत अभियान को ठेंगा दिखा रहा

शांतिवन हाउसिंग सोसायटी में फैली गंदगी

सूरत। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान अन्तर्गत इन दिनों सूरत शहर में चारोप तरफ स्वच्छता के प्रति लोंों में ज ागरुकता पैदाकनरे की कोशश की जा रही है। जिसके लिए डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वाले वाहनों पर स्वच्छा के गति वाले रिकार्डिंग बजते सुनाई दे रहे है। परन्तु सहर के श्रमजीवी बाहुल्य क्षेत्र पांडेसरा इलाके में ऐसी बहुत सारी सोसायटिया है जहां 24 घंटे कचरे का ढेर जमा रहता है। मनपा में शासक पक्ष के नेता भी इसी इलाके से आते है। जिसके जन संपर्क कार्यालय से 500 मीटर की दूरी पर शांतिवन हाउसिंग सोसायटी में फैली कचरे के कारण गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। आशीषनगर के बगल में स्थित इस सोसायटी में पहले कचरा पेटी रखा गया था। जिसे हटा लिया गया। उसकी जगह पर इस क्षेत्र मं घर घर जाकर कचर की गाड़ी कूडा इककठ्ठा करती है। परन्तु यहांके लोगों के स्वभाव तथा व्यवहार में कोई परिवर्त नहीं आया है और ये लो उस जगह पर कचरा फेकन से बाज नहीं आते जिस जगह पर पहले कचरा पेटी हुआ करती थी। ऐसे में डोर टू डोर गार्बेज केलेक्शन क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के लिए नकाफी सिद्ध हो रही है।

जापान मार्केट की पार्कींग से विदेशी शराब भरी कार बरामद

क्राइम ब्रांच ने बुटलेगर अयुब पठान को दबोचा

सूरत। शहर के दिल्ली गेट स्थित जापान मार्केट के चौथे मंजिल की पार्कींग से डीसीबी पुलिस ने ब्रांडेड शराब की बोतलों से भरी कार बरामद की डीसीबी पुलिस ने मिली जानकारी अनुसार जापान मार्केट के चौथी मंजिल पर खड़ी कार जी.जे 05, सी.बी 3825 से 313 बोतल विदेशी शराब बरामद की। पीएसआई गढवी की टीम ने इस मामले में नवसारी बाजार के बुटलेगर अयुब सलिमखान पठान को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरु कर दी है।

गौरतलब है कि अवैध शराब की हेराफेरी करने वाले बुटलेगर पुलिस से बचने के लिए दारू का जत्था इधर उधर छुपाने लगे है ताकी पुलिस की निगाह से बचक अपने धन्धें को अंजाम दे सके। शराब माफियों द्वारा अपनाई जा रही नई तरकीब को पुलिस भांप गई और पुलिस ने जाल विछाकर मुखबीरों की मदद से दारू माफियाओं को पकड़ना शुरु कर दिया है। पुलिस की सक्रीयता से शराब माफियाओं में भय एवं दहशत का माहौल बना हुआ है।

पांडेसार में कीरगर पर चाकू से हमलाकर मोबाइल की लूट का प्रायस

सूरत। पांडेसरा संकटमोचन हनुमान मंदिर के पास मंगलवार की सुबह सवा 7 बजे के करीब पैदल जा रहे सांचा कारीगर को चाकू मार कर घायल कर बदमाश मोबाइल लूटने की कोशिश करने लगे। घायल कारीगर को उपचा के लिए सिविल हास्पीटल में दाखिल कराया गया। मूल बिहार का निवासी सतेन्द्र नामक युवक साचां खाता में काम करता है। मंगलवार की सुबह पांडेसरा के संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने यह कहकर कि कल क्यों तमने मेरे भाई को मारा था रोक लिया। इतना कहते ही स्कूटी पर पीछे बैठे बदमाशन ने सतेन्द्र पर चाकू से हमला कर दिया और उसका मोबाइल छिनने का प्रयास करने लगा। परन्तु सतेन्द्र द्वारा शोर मचाने पर दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। चाकू द्वारा हमला किए जाने से सतेन्द्र लहुलुहान हो गाय। जिसे 108 एम्बूलेंस से सिविल हास्पीटल में ले जाया गया। इस घटना में पुलिस ने दो अज्ञात बदमाशं के विरुद्ध आपाराधिक मामला दर्ज कर खोजबीन शुरु कर दी है।

सूरत। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटलबिहारी वाजपेी के जन्मदिन पर मंगलवार की सुबह शहर भाजपा कार्यालय में बालाजी व्यायामशाला की तरफ से गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए।

ट्रक से 1.32 लाख का शराब मिला

सूरत। ओलपाड़ के करेलीगाम में सिद्ध सोसायटी के पास बिना पास परमिट के शराब की 1056 बोतले पकड़ी गई। पकड़ी गई शराब की कीमत 1.32 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक से शराब की बोतले जप्त कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस की नाकाबंदी को देखकर ट्रक चालक ट्रक छोडकर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध प्रोहिबिशन एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है। जिसके तहत शहर में शराब की तस्करी रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वाहनों की चैकिंग की जा रही है।

सूरत। दक्षिण गुजारत ही नहीं बल्कि सैराष्ट्र तथा उत्तर गुजरात के लोगों के आस्था काकेंद्र सूरत के पाल रोड़ स्थित सिद्धि विनायक गणपति मंदिर परिषर में मंगलवार को अंगास्की चौख पर गणेशार्चतम पूजना का आयोजन किया गया।

प्रवास के दौरान शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की पीटाई से आक्रोशित अभिभावकों ने साधना स्कूल में किया बवाल

सूरत। पुणागाम कारगिल चौक के निकट स्थित साधना स्कलू की तरफ से तीन दिनों के लिए आयोजित राजस्थान प्रवास कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को वासी नाश्ता दिए जाने के बाद विरोध करने वाले विद्यार्थियों की पीटाई का मामला प्रकाश में आने से अभिभावकों ने स्कूल में जाकर जमकर तोड़ फोड़ की।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूणाक्षेत्र की साधना निकेतन स्कूल द्वारा तीन दिनों के लिए राजस्थान प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास के दौरान विद्यार्थियों को शाम को बनाए गए पौवा का नाश्ता दूसरे दिन दिया गया। जिसपर विद्यार्थियों द्वारा विरोध जताने पर 6 विद्यार्थियों को बुरी तरह पटिाई कर दी गई। प्रवास से वापस लौटने पर विद्यार्थियों ने जब यह बात अभिभावकों को बताई तो अभिभावकों ने आक्रोशित हो गए। मंगलवार की सुबह विद्यार्थियों तथा अभिभावकों ने स्कूल में जाकर जमकर तोड़ फोड़ कर हंगामा किया। विद्यार्थियों का यह भी कहना था कि प्रवास पर गए शिक्षकों ने दारू पी रखी थी और नशे की हालत में विद्यार्थियों के साथ कूरता पूर्व व्यवहार किया स्कूल संचालकों को पुलिस बुलानी पड़ी। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और लोगों को समझाबूझा कर मामले को शांत कराया। जबकि शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने किसी के साथ मारपीट नहीं की है। अभिभावक हमपर झूठा आरोप लगा रहे है।

गौरतलब है कि नीजी स्कूल संचालकों ने विद्या के पवित्र मंदिर विद्यालय को अपने मुनाफे के जरिया बना रखा है। नीजी स्कूल के संचालक एक तरफ शिक्षा के नाम पर जहां अभिभावकों से मोटी रमक फी के रुप में वसूल रहे है वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों को न्यूनतम वेतन भी न देकर उनका शोषक कर रहे है। ऐसे में अभिभावकों से मोटी वसूली और शिक्षकों के शोषण के पैसों से संचालक वेसुमार दौलत के मालिक बनते जा रहे है। शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किए जाने के बाद भी सरकार ऐसे संचालकों पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है क्योंकि जयादातर स्कूल नेताओं के या उनके जमचो के है।

एम्ब्रइडरी कारखानेदार से 7.95 लाख की धोखाधड़ी

दो व्यापारियों के विरुद्ध मामला दर्ज

सूरत। एम्ब्रोइडरी जाब वर्क का 7.95 लाख रुपये न चुकाने वाले दो व्यापारियों के विरुद्ध सलाबतपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

सलाबतपुरा पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वराछा के योगी चौक निवासी मनिषभाई देवचन्द भाई रांके ने आरोपी व्यापारी शरद शाम जी राडकिया तथा जशवंत भाई के विरुद्ध धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि आरपीो ने फरियादी के पास से साड़ी पर एम्ब्रोइडर जाब वर्क कराया था जिसका 7,95,143 रुपया बनता है। जिसे दोनों व्यापारियों ने नहीं चुकाकर विश्वास घात किया है। पुलिस ने फरीयादी की शिकायत पर धोखाधडी का मामला दर्ज कर ठग व्यापारियों की तलाश शुरु कर दी है। मंदी के इस माहौल में ठगी के शिकार व्यक्ति के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा है। फरीयादी का कहना है कि व्यापार में जब इस तरह की ठगी होगी तो कैसे एक दूसरे पर भरोसा किया जा सकता है।

जी.जी झड़पिया स्कूल में आयोजित

नई राह नई पहल कार्यक्रम सम्पन्न

सूरत। शहर के अश्विनी कुमार रोड़ स्थित जी.जी झड़पिया स्कूल में 22 से 25 दिसंबर तक आयोजित कार्यक्रम नई राह नई पहल मंगलवार को सम्मपन्न हो गया। 9वीं से 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं के सर्वाघणि विकास के लिए आयोजित इस कार्यक्रम अन्तर्गत ज्ञानात्मक तथा कौशलात्मक विकास के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए।

इस सिविर में अखिल भारतीय बालिका शिक्षण प्रमुख रेखा चुडासभा, जुड़ो कराटे मास्टर हर्षा शाहू, भारतीय शिक्षा चिंतक कल्पेश घनाणी तथा अन्य विशेषज्ञों ने अपने मार्ग दर्शन से छात्राओं में नई चेतना तथा आत्मविश्वास का विकास किया। 22 दिसंबर की शाम 4 बजे से 25 दिसंबर की सुबह 10 बजे तक चली इस कार्यक्रम में 160 छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को सिखाया गया किस प्रकार सोशल मीड़िया का उपयोग करना चाहिए तथा किस प्रकार इसके दुरुपयोग से बचना चाहिए। कार्यक्रम में छात्राओं को भारतीय संस्कृत तथा परम्परा के सरंक्षण तथा संवर्धन के तरीके बताए गए। साथ ही पाश्चात्य सांस्कृति के बुराईयों से बचने के उपाय बताये गए।

वलसाड में प्लेटफार्म की मरम्मत के लिए

रेल्वे की तरफ से 4 दिनों का ब्लाक

सूरत। वलसाड़ रेल्वे प्लेटफार्म पर नान इंटरलोडिंग काम के लिए 28 से 30 दिसंबर तक 4 दिनों के मेगा ब्लाक तक सूरत विरार मेमू ट्रेन को रदद कर दिया गया है। जबकि अन्य ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। वलसाड़ रेल्वे स्टेशन पर बन रहे चौथे तथा पांचवे प्लेटफार्म पर नान इंटरलोडिंग को लेकर पश्चिम रेल्वे द्वारा किए गए मेगा ब्लाकिंग के चलते आगामी शुक्र,शनि तथा रविवार को सूरत वापी पैसेंजर को रदद कर दिया गया है।

रेल्वे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नं. 12944 कानपुर वलसाड़ एकसप्रेस 29 दिसंबर को उधना से कानपुर तक जाएगी। यह ट्रेन वलसाड़ से उधना तक नहीं जाएगी। इसी प्रकार ट्रेन नं. 19051 वलसाड़ मुजफरपुर एक्सप्रेस 29 दिसंबर को उधना से मुजफर पुर तक जाएगी। यह ट्रेन भी वलसाड़ से उधना तक नहीं चलेगी। इस ट्रेन के माध्यम से बड़ी संख्या में नौकरी करने वाले लोग सूरत आते है। इस ट्रेन के रदद होने से यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)